(ख) क्या वर्ष की शेष अवधि के दौरान इस कमी को पूरा करने के लिए कोई विशेष और प्रभावकारी उपाय किए गए हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) 153.25 मिलियन टन।

(ग) 147.28 मिलियन टन का लदान किया गया। टन भार और उपार्जन में क्रमशः 5.97 मिलियन टन और 74.24 करोड़ रुपये की कमी आई है।

(घ) यातायात लक्ष्य से आठ से नौ महीने तक पिछड़ गया हालांकि अतिरिक्त यातायात प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है, व्यस्त काल में और अधिक यातायात की संभावना बहुत क्षीण है।

Cooperative sugar mills in Punjab

*17. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether all the cooperative sugar mills in Punjab are facing a crisis created by non-availability of sugarcane in sufficient quantity;

(b) if so, whether Government propose to take any steps to save the sugar mills in Punjab; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) As on 22-1-1991, co-operative sugar mills in Punjab have crushed 13.24 lakh tonnes of sugarcane during the current 1990-91 season as against 5.80 lakh tonnes on the corresponding date last season. As such all the cooperative sugar mills of the State are not facing a crisis at present due to non-availability of cane.

(b) and (c) Do not arise.

खाद्यान्नों की कमी

*18. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फाल्टी पालिसीज आफ सेंटर काज फूडग्रेन्स स्केर्सिटी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पंजाब प्रशासन द्वारा खाद्यान्नों की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार में गेहूं की कुछ और मात्रा जारी करने के लिए सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार ने अनुरोध किया था कि विभिन्न रोलर फ्लोर मिलों को बेचने के लिए पंजाब में 15 से 20 हजार मीटरी टन गेहूं उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम को जनवरी, और फरवरी 1991 के महीनों के दौरान पंजाब में खुले बाजार में क्रमशः 22,000 मीटरी टन और 30,000 मीटरी टन गेहूं बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता में सुधार करने और मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम को देश के विभिन्न राज्यों में जनवरी और फरवरी, 1991 के प्रत्येक महीने में 5 लाख मीटरी टन गेहूं बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया

है। इसके अलावा, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं का आवंटन दिसम्बर, 1990 में 7.71 लाख मीटरी टन से बढ़ा कर जनवरी, 1991 में 8.07 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन को और बढ़ाकर फरवरी में 9.35 लाख मीटरी टन कर दिया गया। राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टाक रखने की सीमाओं को कम करें और स्टाक रखने की सीमाओं को कड़ाई से लागू करें। इन उपायों से खाड़ी युद्ध के कारण खुले बाजार में उच्चतम सीमा तक पहुंच गेहूं के मूल्यों में कमी आई है।

Proposal to start "Palace on Wheels"

*19. SHRIMATI SATYA BAHIN:
SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a "Palace on Wheels" in the South also on the model of the one run between Delhi and Jaiselmer;

(b) if so, by when it would be introduced and what would be its itinerary;

(c) what would be the cost of running it and what revenue Government expect to earn; and

(d) what is the revenue earned and expenditure incurred on the Delhi-Jaiselmer "Palace on Wheels" at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BHAKTA CHARAN DAS): (a) to (c) A proposal to run "Palace on Wheels' like train in Southern India is under examination, and, a view has yet to be taken.

(d) During 1989-90, Railway earned a revenue of Rs. 1.50 crores on the "Palace on Wheels" and incurred an expenditure of Rs. 1.53 crores on the basis of fully distributed cost and Rs. 0.93 crores on the basis of direct costs.

Requirement of Foodgrains

*20. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the total food stock available with Government and what is the requirement of the various States for different foodgrains;

(b) what is the demand from Maharashtra specially from Bombay city; and

(c) to what extent Bombay's requirement is being met?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) The total stocks of foodgrains (rice and wheat) in the Central Pool as on 1-2-1991 stood at 18.0 million tonnes. The total distribution of foodgrains from Central Pool during 1989-90 was 14.82 million tonnes (rice and wheat).

(b) and (c) The Government of Maharashtra has demanded allocation of 55.000 tonnes of rice and 1,25.000 tonnes of wheat from the Central Pool for the Public Distribution System for the month of March, 1991. The State has been allocated 45.000 tonnes of rice and 1,20,000 tonnes of wheat. The distribution of foodgrains within the State is the responsibility of the State Government.

Setting up of National Potato Board

†SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a National Potato Board;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the concerned States have been consulted in this matter,